



CHETANA  
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal

(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))

Impact Factor  
SJIF 2023 - 7.286



Prof. A.P. Sharma  
Founder Editor, CIJE  
(25.12.1932 - 09.01.2019)

## भारत की अध्यक्षता में जनोन्मुख बनता जी-20

डॉ. शारदा देवी

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान,  
राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर

Email-saru.sdc2001@gmail.com, Mobile-9772107743

First draft received: 12.02.2024, Reviewed: 15.02.2024, Final proof received: 18.02.2024, Accepted: 18.03.2024

### सार-संक्षेप

विश्व की बदलती आर्थिक परिस्थितियों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 80 फीसदी से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G-20 की अध्यक्षता भारत की वैश्विक आर्थिक नीतियों सतत और समावेशी विकास की स्वीकार्यता है। G-20 का गठन 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद आर्थिक स्थिरता लाने के लिए किया गया था। 2008 के वित्तीय संकट के बाद G-20 के सदस्य राष्ट्रों के सम्मेलनों के आयोजन की शुरुआत हुई जिसमें आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी चर्चा होने लगी। नवम्बर 2022 में इंडोनेशिया के बाली शहर से शुरू हुई भारत की अध्यक्षता में G-20 ने सफलता के नये अध्याय जोड़े।

भारतीय संस्कृति के ध्येय वाक्य "वसुधैव कुटुम्बकम्" यानि एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य को सम्मेलन की थीम बनाकर वैश्विक आर्थिक नीतियों का आधार बनाने की पहल नई-दिल्ली से की गयी। भारत की अध्यक्षता में G-20 लोकतांत्रिक और जनता के सम्मेलन का रूप लेता नजर आया। वर्ष भर की अध्यक्षता में बैठकों का दौर केवल नई दिल्ली तक सीमित नहीं रहा बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विविधता में एकता और सहयोगी संघवाद की झलक दिखाई दी। पूरे साल नागरिक संगठन और जमीनी स्तर के नेता, महिलाएं युवा और यहां तक कि स्कूल के बच्चे इस आयोजन से जुड़े। भारत के नेतृत्व में अफ्रीकी संघ को G-20 का सदस्य बनाना भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाला कदम था। मानव केन्द्रित विकास पर जोर देते हुए भारत ने अपनी अध्यक्षता में G-20 को आर्थिक सुरक्षा परिषद बनाने पर जोर दिया। नई दिल्ली सम्मेलन ने आतंकवाद से लेकर आर्थिक संवृद्धि, जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, समावेशी और सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा जैसे- वैश्विक मुद्दों के समाधान के नये रास्ते प्रस्तुत किये। भारत को G-20 की अध्यक्षता ऐसे मौके पर मिली, जब कोविड-19 महामारी के बाद उसे जबरदस्त आर्थिक रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए पूरी दुनिया में सराहा जा रहा था। भारत ने अपने नेतृत्व में नई दिल्ली घोषणा प्रपत्र के माध्यम से आने वाले वर्षों के लिए एक मानव केन्द्रित प्रगति का विजन प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने G-20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपते हुए कहा कि समस्त लोगों, धरती, शांति और समृद्धि के लिए हमारे सामूहिक कदमों की गूंज आने वाले वर्षों में निरंतर सुनाई देती रहेगी।

यह शोध पत्र अपनी अध्यक्षता के दौरान जी-20 को जन-उन्मुख बनाने में भारत द्वारा निर्भाई गई परिवर्तनकारी और प्रभावशाली भूमिका पर प्रकाश डालता है। भारत की अध्यक्षता में जी-20 ने न केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक स्वरूप प्राप्त किया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जनता का सम्मेलन बन गया। जी-20 के मंच से भारत ने विश्व के सामने पर्यावरण अनुकूल जनकेन्द्रित नीतियां प्रस्तुत की जो अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान बताती हैं।

**मुख्य-शब्द :** जी-20, भारत, सतत विकास, अध्यक्षता, लोकतांत्रिक, वैश्विक दक्षिण, वसुधैव कुटुम्बकम् आदि.

### परिचय

बहुपक्षीय सहयोग, समन्वय एवं वार्ताओं से वैश्विक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसी सम्प्रत्यय के साथ 1997 के एशियन वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में 19 प्रमुख देशों और यूरोपीय संघ द्वारा जी-20 का गठन किया गया। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक आयोजित की गयी जिसमें वैश्विक वित्तीय स्थिरता स्थापित करने, संकट को टालने के उपाय, सदस्य देशों के आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। 2008 के आर्थिक संकट के बाद जी-20 के सदस्य राष्ट्र प्रमुखों के सम्मेलनों की शुरुआत हुई और इसे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच नाम दिया गया। जी-20 विकसित और विकासशील देशों को एक मंच पर लाकर दुनिया के आर्थिक मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करता है।

जी-20 का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के बीच चक्रानुक्रम में चलता रहता है जो एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करता है। वर्तमान अध्यक्ष देश द्वारा तत्काल भूतपूर्व और भावी अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना (ट्राइको) समूह की अनुकूलता एवं निरन्तरता को सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2023 में जी-20 ट्रोइका में इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत शामिल थे। जी-20 दो तरीके से कार्य करता है, एक वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक गवर्नरों की बैठके, दूसरा शेरपा बैठके। जी-20 की कार्यवाही का नेतृत्व शेरपाओं द्वारा ही किया जाता है जो सदस्य देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि होते हैं। ये शेरपा ही शिखर सम्मेलन के एंजेडे पर विचार-विमर्श करने और पूरे वर्ष होने वाली वार्ताओं की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार हैं। जी-20 की कार्यसूची में प्रमुखतः वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत और समावेशी विकास, सामाजिक - आर्थिक प्रगति और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे विषय शामिल होते हैं। समूह वैश्विक आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए सदस्य देशों के बीच नीति समन्वय बनाता है और वित्तीय नियमों के पालन को बढ़ावा देता है। जी-20 का प्रमुख उद्देश्य एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना बनाना है।

16 नवम्बर 2022 को जी-20 बाली (इंडोनेशिया) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जी-20 की अध्यक्षता सौंपी गयी थी जो 1 दिसम्बर 2022 से शुरू होकर 30 नवम्बर 2023 तक जारी रही। यह पहला ही अवसर था जब भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिली। कोविड-19 महामारी का सामना पूरे विश्व में भारत ने जिस तरीके से किया वो राष्ट्रों के लिए एक उदाहरण था। भारत ने न केवल स्वयं का पुनर्निर्माण किया बल्कि अन्य देशों को वैकसीन

पहुँचाकर जो सहायता की वो भारत की वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से ही प्रेरित था। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध भारत जैसे उभरते राष्ट्र का जी-20 का अध्यक्ष बनना विकासशील देशों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत की जी-20 की अध्यक्षता का विषय 'वसुधैव कुटुम्बकम'— एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' था जिसने जी-20 को एक नयी सार्थकता प्रदान की। यह विषय पर्यावरणीय संतुलन, स्वच्छ व सादगीपूर्ण जीवन शैली और सतत विकास को अर्थ प्रदान करता है। भारत की अध्यक्षता, में जी-20 की कार्यसूची में LiFE आन्दोलन, जलवायु संरक्षण, समावेशी विकास, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, सतत विकास के 2030 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, सामाजिक-आर्थिक न्याय और महिलाओं द्वारा विकास कार्यों का नेतृत्व एवं क्षेत्रीय एकता एवं अखंडता का सम्मान कर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सद्भाव को बढ़ाना आदि शामिल किये गये थे।

### शोध की आवश्यकता और महत्व

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर होने वाले सम्मेलनों और कार्यक्रमों से विश्व का परिदृश्य बदलता रहता है जिस पर निरन्तर अध्ययन की आवश्यकता रहती है। जी-20 की भारत की अध्यक्षता ने न केवल विदेशी परिदृश्य को बल्कि घरेलू परिदृश्य को भी पुनर्गठित किया। भारत की अध्यक्षता में जी-20 ने कुलीनों के सम्मेलन से जन-सम्मेलन बनने तक का एक साल का सफर तय किया, इस दौरान भारत वैश्विक मंच का केन्द्र तो बना ही, साथ ही वसुधैव कुटुम्बकम का आदर्श विश्व के सामने प्रस्तुत कर वैश्विक समस्याओं के समाधान की राह दिखायी, इसलिए भारत की जी-20 की अध्यक्षता के परिणामों पर अध्ययन की आवश्यकता थी।

प्रस्तुत शोध में जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तुत किये गये सुझावों और कार्यों का अध्ययन किया गया है। भारत ने न केवल वैश्विक दक्षिण की आवाज को ताकत दी बल्कि विश्व के सामने मानव-केन्द्रित विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत की अध्यक्षता को और भी खास बनाने वाला कारक था, 135 राष्ट्रीयताओं की भागीदारी के साथ ही पूरे देश से जनभागीदारी का व्यापक समावेश। प्रस्तुत शोध भारत की अध्यक्षता में जी-20 के लोकतंत्रीकरण रूप लेने से लेकर नागरिकता के मानवता बनने के परिणामों की व्याख्या करता है।

### शोध का उद्देश्य

- जी-20के सम्मेलन में बढ़ी जन-भागीदारी के परिणामों का अध्ययन करना।
- भारत की अध्यक्षता के दौरान जी-20 में आये बदलावों का अध्ययन करना।
- विकासशील देशों की आवाज को ताकत देने के भारत के प्रयासों का अध्ययन करना।
- यह बताने का प्रयास करना कि वैश्विक समस्याओं का समाधान समावेशीकरण और बहुपक्षवाद की नीति अपनाकर किया जा सकता है।

### शोध की प्रविधि

शोध अध्ययन के लिए ऐतिहासिक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है। तथ्यों का समावेश कर अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है। द्वितीय आकड़ों का प्रयोग किया गया है जिसमें इस विषय पर प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं, वैश्विक संस्थाओं व भारतीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित विभिन्न विश्लेषणात्मक आकलन तथा पुस्तकों में प्रकाशित जानकारियों का प्रयोग किया है।

### जी-20 को जन-उन्मुख बनाने की भारत की पहल

जब वर्ष 2022 में भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिली उस समय विश्व कई चुनौतियों कोविड-19 महामारी के विनाशकारी परिणाम, बढ़ते जलवायु खतरों, वित्तीय अस्थिरता, विकासशील देशों में ऋण संकट, कमजोर होता बहुपक्षवाद, रूस-यूक्रेन युद्ध तथा देशों के बीच बढ़ते संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था। बाली में अध्यक्षता ग्रहण करते समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि हमारी अध्यक्षता समावेशी, निर्णायक और कार्यवाही-उन्मुख होगी तथा सामूहिक कार्यवाही पर ध्यान केन्द्रित करेगी। इसी अनुरूप भारत ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अपने एक वर्ष की अध्यक्षता में जी-20 को जिस मंजिल पर पहुँचाया वह असाधारण था। भारत की जी-20 की अध्यक्षता का विषय 'वसुधैव-कुटुम्बकम'— एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य था जिस पर ध्यान करते हुए भारत ने टिकाऊ और समावेशी विकास तथा स्वच्छ और हरित दुनिया के लिए भारत में वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। 8 नवम्बर 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 का लोगों कमल का फूल लॉन्च किया था जिसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया जो हमारे पृथ्वी समर्थक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। इस दौरान भारत ने LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पर जोर दिया ताकि बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।

भारत ने अपनी विविधता, समावेशी परम्पराओं और सांस्कृतिक समृद्धि के अनुरूप जी-20 के आयोजन को लोक आयोजन बना दिया। भारत ने अपने संविधान की प्रस्तावना के शब्द 'हम भारत के लोग' के समान सम्पूर्ण जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर जनता का जी-20 बना दिया। अंजमान निकोबार के स्वराज द्वीप से शुरू हुयी बैठको के दौर ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय किया। भारत की अध्यक्षता के दौरान जितने कार्यक्रम आयोजित हुये,

उनकी संख्या भारत की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुम्बकम और विविधता में एकता को प्रदर्शित करती है। भारत की अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक 4.7 दिसम्बर 2022को राजस्थान के उदयपुर शहर में आयोजित हुई। इस बैठक में विविध मुद्दों पर आम सहमति बनाने के साथ-साथ प्रतिनिधियों को राजस्थान की सांस्कृतिक कला प्रदर्शनियाँ, विश्व धरोहर स्थल कुम्भलगढ किले और रणकपुर मंदिर का भ्रमण करवाकर एक अद्वितीय भारत का चित्र प्रस्तुत किया गया। भारत के शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक में भविष्य में होने वाली बैठको के लिए विषय और एंजेडा तय किया गया।

एक वर्ष की अध्यक्षता में कुल 227 बैठके 28 राज्यों और 8 केन्द्रशासित प्रदेशों के 60 शहरों में आयोजित की गयी। जिनमें 135 राष्ट्रीयताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान 21 मंत्रिस्तरीय बैठके, 11 सम्पर्क समूह सम्मेलन, 6 पहल सम्मेलन, 4 शेरपा बैठके आयोजित की गयी जिसमें देश के कोने-कोने से जन भागीदारी रही। जी-20 के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक 40 कार्यशालाएं आयोजित हुईं। इन कार्यशालाओं में शेरपा ट्रैक वर्किंग समूह की 13 बैठके कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यावरण, आपदा-प्रबंधन, व्यापार व निवेश, स्वास्थ्य, संस्कृति, भ्रष्टाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यटन पर आयोजित की गयी। इसके अलावा वित्तीय ट्रैक की 8 बैठके, 6पहल समूह की बैठके, 1 विदेश मंत्रियों की बैठक, एक महिला सशक्तिकरण पर मंत्रियों की बैठक आयोजित की गयी। सबसे महत्वपूर्ण बैठके सम्पर्क समूह की थी जिन्होंने भारतीयता के प्रत्येक पक्ष को शामिल किया, फिर चाहे वो यूथ 20 हो, वूमन 20 हो या थिंक 20। भारत ने जी-20 के 9 अतिथि देशों के अलावा 32 अतिरिक्त देशों 11 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी वर्किंग ग्रुप की बैठकों में आमंत्रित किया जो कि भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमर्श में बहुपक्षवाद के समर्थन को दर्शाता है।

भारत की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम सम्मेलनों में प्रस्तुत किये गये। भारत की ऐतिहासिकता के सांस्कृतिक प्रदर्शन और भ्रमण आयोजित किये गये। भारतीय संस्कृति एवं विरासत की झलक पेश करते हुए चांदी के बर्तनों में मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे गये। भारत की स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकृतियों का प्रदर्शन करने वाले 18000 से अधिक कलाकारों की भागीदारी के साथ 300 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये। भारत ने जी-20 के सम्मेलनों में सम्पूर्ण सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित की। सार्वजनिक भागीदारी के दौरान दो विश्व रिकॉर्ड बनाये गये, एक था वाराणसी में जी-20 विजय में 800 स्कूलों के 1.25 लाख छात्रों की भागीदारी, दूसरा 450 लंबानी कारीगरों ने अपनी कला और शिल्प कौशल का 1800 पेज का अद्भूत संग्रह बनाया। कार्य समूहों ने जनभागीदारी बढ़ाने के लिए नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कई गतिविधियाँ आयोजित की। ज्ञानवर्धक जी-20 विश्वविद्यालय सम्पर्क व्याख्यान श्रृंखला से लेकर शैक्षिक संस्थानों में विशेष जी-20 सत्र प्रमुख त्योहारों में जी-20 मंडप, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, सेल्फी प्रतियोगिताएं और मनोरम कहानियों तक कई तरह की रोचक गतिविधियों ने जी-20 को जनता की आवाज बना दिया। कॉरपोरेट, नागरिक संगठन, महिलाएं, युवा और यहां तक कि स्कूल के बच्चे इस आयोजन से जुड़े। कुल मिलाकर लगभग 7करोड़ लोगों ने जी-20 के कार्यक्रमों में भाग लिया। अकेले नागरिक-20 पहल समूह से दुनिया भर से करीब 45 लाख लोग जुड़े। जी-20 कार्यक्रमों में न केवल नागरिक समाज बल्कि स्वयं सहायता समूहों, छोटे ग्रामीण पहलों और स्थानीय समूहों को एक मंच पर लाया गया जिनका अब तक ऐसे सम्मेलनों से कोई सम्बन्ध नहीं था।

जन भागीदारी का स्तर केवल जनभागीदारी की संख्या तक सीमित नहीं रहा बल्कि स्वदेशी तकनीके और समस्या समाधान की प्रणालियां जन-केन्द्रित बनकर उभरी। इन कार्यक्रमों ने वैश्विक मुद्दों को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया और स्थानीय विचारों को वैश्विक स्तर तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की। युवा-20 समूह ने देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों में यहां तक कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ रण के दूर-दराज के गांवों और कस्बों में 400 से अधिक युवा 20 कार्यक्रम आयोजित किये जिसने वैश्विक मुद्दों पर भारतीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया। इसी तरह से मजदूर-20 का आयोजन हुआ जिसमें ट्रेड यूनियन-एनएफआईटीयू, टीयूसीसी, इंटक ने एक मंच साझा किया। इसमें सुरक्षा सार्वभौमिककरण, सामाजिक सुरक्षा निधि, अनौपचारिक श्रमिकों और महिला मजदूरों से सम्बन्धित भविष्य के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। मजदूर-20 कार्यक्रमों में स्वच्छता सिपाही से लेकर यूरेनियम खदानों के श्रमिकों, घरेलू कामगारों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गिग श्रमिक भी शामिल हुये। मजदूर-20 कार्यक्रमों में महिला केन्द्रिता गतिविधियों आयोजित की गयी जिनमें 5000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सेदारी ली।

जी-20 के कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय संस्कृति और विकाससात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 'ग्राम हाट' का आयोजन किया गया। ऐसी ही एक झलक पटना में मजदूर 20सम्मेलन में देखने को मिली जिसमें स्थानीय कलाकारों ने बावन बूटी से लेकर कालीन बुनाई तक के हस्तशिल्प स्टॉल लगाये। इन कार्यक्रमों में महिला नेतृत्व वाली विकाससात्मक पहलों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान और लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। देश के कोने - कोने में आयोजित हुयी जी-20 की बैठकों ने वैश्विक समुदाय को इस बात से अवगत करा दिया कि नई दिल्ली और मुम्बई से परे भी एक भारत है। इन बैठको के दौरान भारत और शेष भारत जिस तरीके से एक वैश्विक मंच पर उपस्थित हुए वो हमारी समृद्धिशाली संस्कृति 'विविधता में एकता' का परिचायक था।

जी-20 न केवल राष्ट्रीय स्तर पर जनोन्मुख बना बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह रूप स्पष्ट नजर आया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह कहना कि हमारी अध्यक्षता में जी-20 की प्राथमिकताएं केवल जी-20 के भागीदार देश ही तय नहीं करेंगे बल्कि वैश्विक दक्षिण के हमारे साथियों के परामर्श से भी तय की जायेगी, बहुपक्षवाद की एक नयी शुरुआत थी। इसीलिए भारत द्वारा वर्ष 2023 के प्रथम महीने में पहली 'वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट' आयोजित की गयी। ग्लोबल साउथ वो देश है जो विकास को लेकर समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ इन देशों का साझा भविष्य रहा है। इस बैठक में 125 देशों ने भाग लिया। जी-20 के माध्यम से भारत ने वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज बनने का कार्य किया। भारत का मानना है कि आज दुनिया जिन संकटों का सामना कर रही है, उनमें सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव ग्लोबल साउथ डोल रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत ने यह साबित कर दिया कि भारत वैश्विक विकास में विकासशील देशों की समान हिस्सेदारी चाहता है।

भारत ने इस सम्मेलन में विकासशील देशों को साथ लेकर चलने की नीति अपनायी। भारत का मानना है कि अधिकांश वैश्विक चुनौतियाँ वैश्विक दक्षिण द्वारा नहीं बनायी गयी लेकिन फिर भी वे हमें अधिक प्रभावित करती हैं। हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक जैसी रही है जिसमें हमने उपनिवेशवाद के खिलाफ एक-दूसरे का समर्थन किया है, आज फिर नयी विश्व व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं जो हमारे नागरिकों को विकास की ओर अग्रसर करे। आपकी आवाज भारत की आवाज है और आपकी प्राथमिकताएं हमारी प्राथमिकताएं हैं। वैश्विक दक्षिण का सम्मेलन आयोजित कर भारत ने वैश्विक साझेदारी और सहयोग का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। भारत ने यह माना कि ऊर्जा, जलवायु, खाद्य जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान केवल वैश्विक उत्तर ही नहीं बल्कि वैश्विक दक्षिण भी दुनिया के भविष्य के निर्धारण का हिस्सा बनने का हकदार है।

### प्रगति मैदान (नई दिल्ली) – मानव-केन्द्रित वैश्विक समृद्धि, सतत विकास, लोकतांत्रिकरण, समावेशीकरण, एकीकरण और बहुपक्षवाद का नया प्रतीक

भारत की अध्यक्षता में हुए जी-20 के 18 वें शिखर सम्मेलन ने सफलता के कई नये अध्याय जोड़े। सम्मेलन के विषय— एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए भारत में विश्व के सामने मानव केन्द्रित प्रगति का विजन प्रस्तुत किया। प्रगति मैदान में भारत मंडप तैयार किया गया जिसके हर कोने में भारत की समृद्धिशाली संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता, बेजोड कलाओं (मुर्तिकला, स्थापत्य, वास्तुकला), संगीत विरासत और लोकतांत्रिक परम्पराओं के प्रतीक चिह्न सजाये गये।

55 सदस्यीय अफ्रीकी संघ को जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना भारत की समावेशीकरण और लोकतांत्रिकरण की नीति का परिणाम था। विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय मंच होते हुए भी जी-20 वैश्विक आवादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से से दूर था। भारत के इस निर्णय से न केवल भारत की वैश्विक साख मजबूत होगी बल्कि अफ्रीका संघ के विश्व अर्थव्यवस्था में आर्थिक भागीदारी के अवसर बढ़ेंगे। भारत की अध्यक्षता में जैव ईंधन को ऊर्जा का प्रमुख घटक स्थापित करने के लिए 'वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन' की पहल की गयी ताकि रोजगार बढ़ाये जा सके। इस गठबंधन की शुरुआत 9 अरम्भिक सदस्यों भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गयी। जी-20 के सदस्यों और 12 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर अपनी सहमति जतायी। विकासशील देशों में बुनियादी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए भारत – मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। भारत के वित्तीय समावेशन के आधार डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा की जी-20 सदस्यों द्वारा सराहना की गयी।

### नई दिल्ली घोषणा पत्र

- समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्यवाही-उन्मुख और निर्णायक जैसे सिद्धान्तों पर कार्य करने की भारत की प्रतिबद्धता पर आधारित नई दिल्ली घोषणा-पत्र को जी-20 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। घोषणा-पत्र के अहम बिन्दु प्रमुख थे इस घोषणा पत्र में मजबूत, संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास करने की बात की गई।
- 2030 तक स्थायी विकास के लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रगति में तेजी लाने के सात-साल की कार्य-योजना प्रस्तुत की गयी।
- एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य की भावना के तहत हमारी सदियों पुरानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE) को अपनाने का आह्वान किया गया।
- विकासशील देशों में विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए दी जाने वाली पूंजी को अरबों से खरबों तक बढ़ाने का आह्वान किया गया।
- एकीकृत, संतुलित, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और समावेशी, आर्थिक विकास के लिए हरित विकास समझौता किया गया जिसमें उपभोग जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर और उत्पादन पृथ्वी के संरक्षण को ध्यान में रखकर करने पर बल दिया गया।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पर्यावरण निधि में और अधिक पूंजी लगाने का आह्वान विकसित देशों से किया गया।

- नई दिल्ली घोषणा में स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायोचित और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के प्रति वचनबद्धता जताई गई, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और बाजार की स्थिरता के लिए ऊर्जा संसाधनों की अबाध आपूर्ति बनाये रखने पर जोर दिया गया।
- जी-20 देशों ने वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने पर सहमति जताई।
- शून्य और कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन के उत्पादन में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की गयी और इसके लिए वैश्विक बाजार विकसित करने पर जोर दिया गया।
- समावेशी दुनिया के निर्माण के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं के पुनर्गठन पर जोर दिया गया ताकि न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
- बहुपक्षीय विकास बैंको को अधिक प्रभावी और बड़ा बनाने पर सहमति जतायी गयी ताकि कमजोर देशों की मदद की जा सके।
- नई दिल्ली घोषणा पत्र में महिला-पुरुष समानता पर जोर देकर महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को सबसे अधिक व्यापक स्थान दिया गया। निर्णय निर्माताओं के रूप में उनकी पूर्ण और समान भागीदारी के साथ खाद्य सुरक्षा, पोषण को सुनिश्चित करने के अलावा महिला – पुरुषों के बीच डिजिटल अंतर को 2030 तक आधा करने का लक्ष्य रखा गया।
- स्वास्थ्य सेवाओं को न्यायसंगत, सतत और समावेशी बनाने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जतायी गयी। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का अवलोकन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया।
- नई दिल्ली घोषणा में आंतकवाद के सभी रूपों की निन्दा की गयी तथा मानवाधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया।
- सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी से बचना चाहिए इसलिए हम यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और टिकाऊ शान्ति का समर्थन करने वाली पहलों का स्वागत करेंगे।

### भारत की जनोन्मुख कार्यनीतियों के प्रभाव → अन्तर्राष्ट्रीय-राष्ट्रीय

भारत की जी-20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य जनकल्याण की नीतियों पर ही आधारित था। भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारत ने विश्व को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाये जाने की सीख दी। 'मौजूदा दौर जंग का नहीं है' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह गूँज विश्व के हर कोने तक पहुँची है। कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकटों के बीच भारत ने अध्यक्षता के दौरान एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया। भारत ने विकास को नये तरीके से मानव, पृथ्वी और समृद्धि के रूप में परिभाषित किया। इसलिए भारत ने विश्व के सामने जीडीपी केन्द्रित प्रगति नहीं बल्कि मानव केन्द्रित प्रगति का विजन प्रस्तुत किया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता की पहचान मिली और एक ऐसे देश के रूप में उभरा जो अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब भारत ने कतार में सबसे पीछे खड़े सदस्य तक पहुँचने की सर्वोदय से अंत्योदय की भावना का पालन करते हुए अफ्रीकी संघ को जी-20 का सदस्य बनाने की घोषणा की तब भारत वैश्विक जननायक के रूप में दिखायी दे रहा था।

जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा वैश्विक दक्षिण की बैठक बुलाना हो, स्त्री-पुरुष की समान भागीदारी की पुरजोर वकालत हो, वैश्विक संस्थाओं में समान और न्याय संगत प्रतिनिधित्व की अपील हो, अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव अपनाने पर जोर हो या आंतकवाद के सभी रूपों की निन्दा हो, भारत की लोकतंत्र की जननी की छवि सुदृढ़ हुई।

राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जी-20 के सम्मेलन को 'जनता का सम्मेलन' बना दिया। सम्मेलन के कार्यक्रमों के दौरान भारत के सभी विभागों में कार्य करने की एकजुटता दिखायी दी। देश के प्रत्येक राज्य और संघशासित क्षेत्र में जी-20 का कार्यक्रम आयोजित हुआ, फिर वह राज्य भाजपा शासित था या कांग्रेस शासित। इस दौरान भारत की संघीय व्यवस्था ने सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की नयी मिसाल पेश की। भारत की अनूठी पारम्परिक चिकित्सा पद्धति, मोटे अनाज आधारित खाद्यान्न प्रणाली और लोक संस्कृति पर आधारित उद्यमों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान मिली। विश्व स्तर पर भारत 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' और 'मॉडल ऑफ डेवेलपिटी' के रूप में उभरा।

### निष्कर्ष

वैश्विक नेतृत्व की बात हो या क्षेत्रीय और वैश्विक सम्मेलनों के सफल आयोजन की, विश्व के देशों की नजर विकसित देशों या कहे विश्व उत्तर के देशों की ओर जाती है लेकिन जी-20 के 18वें शिखर सम्मेलन को भारत ने अब तक का सबसे सफल और समावेशी सम्मेलन बना दिया। विश्व की 135 राष्ट्रीयताएं, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, सरकारें और आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक क्षेत्र के लोगों खास तौर से विकासशील देशों की भागीदारी से भारत के नेतृत्व में जी-20 जनता का जी-20 दिखायी दिया। इस दौरान भारत ने विश्व को अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और लोकतांत्रिक परम्पराओं से अवगत कराया। जी-20 की अध्यक्षता भारत के लिए वैश्विक

मामलों में अपना नेतृत्व प्रदर्शित करने की चुनौती और अवसर दोनों ही थे, भारत ने अपनी वित्तीय, राजनीतिक और मानवीय पूँजी लगाकर अपनी अध्यक्षता को असाधारण बना दिया।

भारत ने अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को जी-20 का सदस्य बनाकर जी-21 बना दिया। दिल्ली घोषणा पत्र में भारतीय संस्कृति के ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुम्बकम् के अनुसार वैश्विक समस्याओं को सबकी समस्यायें मानकर समाधान करने की घोषणा की गयी। नई दिल्ली घोषणा पत्र से भारत दुनिया की व्यवस्था का निर्माता बनकर उभरा है। जी-20 आयोजनों ने देश के विभिन्न हिस्सों में ढांचागत, सूचनात्मक और संस्थागत विकास में योगदान दिया है, उन्होंने न केवल नागरिक समाज को बल्कि स्वयं सहायता, छोटे ग्रामीण पहलु और स्थानीय कार्यवाही समूहों को एक साथ लाया गया जो वैश्विक संवाद से अलग थे। इन कार्यक्रमों से समाज के विभिन्न वर्गों को अधिक अवसर मिले और सामाजिक – आर्थिक गतिशीलता में बढ़ोतरी हुई।

भारत की जी-20 अध्यक्षता कई मायनों में अद्वितीय रही है। भारत ने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और प्रमुख समस्याओं को विश्व के सामने प्रस्तुत किया, वैश्विक दक्षिण की आवाज को ताकत दी है। भारत ने जलवायु सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना हो वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, ऊर्जा नवीनीकरण स्त्रोत बढ़ाने हो या सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, आतंकवाद से निपटना हो, महिलाओं की निर्णय निर्माण में भूमिका बढ़ानी हो, ऐसे सभी क्षेत्रों को अपनी कार्यवाही में शामिल किया। भारत की अध्यक्षता को ओर भी खास बनाने वाला कारक था – पूरे देश से जनभागीदारी का व्यापक समावेश और यह समावेशन केवल सरकार के उच्चतम स्तर तक ही सीमित नहीं था, विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सक्रिय जन भागीदारी से भारत की अध्यक्षता में जी-20 जन जी-20 बन गया।

जी-20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2024 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपकर कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि वे समर्पण और दूरदर्शिता के साथ इसका नेतृत्व करेंगे और वैश्विक एकता और समृद्धि को आगे बढ़ायेंगे। वर्ष 2024 और 2025 में जी-20 की अध्यक्षता करने वाले ब्राजील और अफ्रीका से यह अपेक्षा की जाती है कि दिल्ली शिखर सम्मेलन के परिणामों को परिवर्तनकारी पथ पर आगे बढ़ाये।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. pmindia.gov.in फरवरी, 2023
2. नवोदित शक्तावत, spmrf.org, मार्च, 2023
3. भारत की जी-20 अध्यक्षता : विश्व को समावेशी और सतत विकास की ओर ले जाने का एक अवसर, एशियाई विकास बैंक, जून, 2023
4. अमित त्यागी, द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, सितम्बर, 2023
5. जी-20 और भारत, इंडियन एक्सप्रेस सितम्बर, 2023
6. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली, सितम्बर, 2023
7. प्रशान्त पांडे, नई दुनियां, सितम्बर, 2023
8. कृष्ण गोपालन, बिजनेस टुडे, सितम्बर, 2023
9. नवीन कुमार पाण्डेय, टाइम्स ऑफ इंडिया, सितम्बर, 2023
10. India's G-20 Presidency: A Synopsis, www.g20.in, 2023
11. Soumya Bhowmick, www.orfonline.org.hindi, सितम्बर, 2023
12. बिजनेस स्टैंडर्ड, नवम्बर, 2023
13. प्रेस नोट, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली, नवम्बर 2023
14. www.orfonline.org.hindi, दिसम्बर, 2023